सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय Office of the Commissioner

केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय Central GST, Appeals Ahmedabad Commissionerate जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015

GST Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-380015 Phone: 079-26305065 - Fax: 079-26305136

E-Mail: commrappl1-cexamd@nic.in
Website: www.cgstappealahmedabad.gov.in



By SPEED POST

DIN:- 20240164SW0000999B57

(क)	फ़ाइल संख्या / File No.	GAPPL/COM/STP/4270/2023/1006 70 1011
(ख)	अपील आदेश संख्याऔर दिनांक / Order-In –Appeal and date	AHM-EXCUS-001-APP-248/2023-24 and 30.01.2024
(ग)	पारित किया गया / Passed By	श्री ज्ञानचंद जैन, आयुक्त (अपील) Shri Gyan Chand Jain, Commissioner (Appeals)
(ঘ)	जारी करने की दिनांक / Date of Issue	31.01.2024
(ङ)	Arising out of Order-In-Original No. 321/WS08/AC/KSZ/2022-23 dated 24.02.2023 passed by The Assistant Commissioner, CGST, <u>Division-VIII</u> , Ahmedabad South.	
(च)	अपीलकर्ता का नाम और पता / Name and Address of the Appellant	M/s. Rajesh Govindbhai Mehta, B-104, Tulip Citadel, Near Shreyas Railways, Ambawadi, Ahmedabad – 380 015.

कोई व्यक्ति इस अपील-आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश के विरुद्ध हो सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way.

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन:-

Revision application to Government of India:

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 को की जानी चाहिए:-

A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(क) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार मे हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयों के उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(घ) अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं 2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(3) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम होतो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपीलः-Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (2) उक्तलिखित परिच्छेद में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004।

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2ndfloor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. In case of appeals other than as mentioned above para.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संषोधित की अनुसूची -1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू 6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) एके प्रति अपीलो के मामले में कर्तव्यमांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा कर्तव्य की मांग (Duty Demanded)।

- (1) खंड (Section) 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (2) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशिय;
- (3) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि।

यह पूर्व जमा ' लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना मेंए अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(6) (i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Rajesh Govindbhai Mehta, B-104, Tulip Citadel, Near Shreyas Railways, Ambawadi, Ahmedabad – 380 015 (hereinafter referred to as the "appellant") against Order-in-Original No. 321/WS08AC/KSZ/2022-23 dated 24.02.2023 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Deputy Commissioner, Central GST, Division VIII, Ahmedabad South (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

- Briefly stated, the facts of the case are that the appellant are 2. holding PAN No. ABDPM0194R. On scrutiny of the data received from the Central Board of Direct Taxes (CBDT) for the F.Y. 2015-16, it was noticed that the appellant had earned income of Rs. 16,92,400/- during the F.Y. 2015-16, which was reflected under the heads "Sales / Gross Receipts from Services (Value from ITR)" filed with the Income Tax department or total amount paid/credited under Section 194C, 194I, 194H, 194J" as provided by the Income Tax Department for the financial year 2015-16. Accordingly, it appeared the appellant had earned the said substantial income by way of providing taxable services but had neither obtained Service Tax registration nor paid the applicable service tax thereon. The appellant were called upon to submit copies of required documents for assessment for the said period. However, the appellant had not responded to the letters issued by the department.
- 2.1 Subsequently, the appellant were issued Show Cause Notice No. CGST/WS0803/O&A/TPD(15-16)/ABDPM0194R/2020-21 dated 22.12.2020 wherein:
- a) Demand and recover an amount of Rs. 2,45,398/- under proviso to Sub Section (1) of Section 73 of the Act along with interest under section 75 of the Finance Act 1994 (hereinafter



- referred to as 'the Act').
- b) Impose penalty under the provisions of Section 77(1), 77(2) and 78 of the Act.
- 2.2 The Show Cause Notice was adjudicated ex-parte vide the impugned order by the adjudicating authority wherein:
- a) The demand of service tax amounting to Rs. 2,45,398/- was confirmed under section 73(1) of the Act by invoking extended period along with interest under section 75 of the Act.
- b) Penalty amounting to Rs. 10,000/- was imposed under section 77(1) of the Act as they failed to obtain service tax registration.
- c) Penalty amounting to Rs. 2,45,398/- was imposed under 78 of the Act.
- d) Penalty of Rs. 10,000/- was imposed on the appellant under the provision of the Section 77(2) of the Act for failure to assess the tax due on the services provided by them and furnish a return in the format of ST-3 return within the specified time.
- 3. Being aggrieved with the impugned order passed by the adjudicating authority, the appellant have preferred the present appeal, inter alia, on the following grounds:-
 - ➤ That the SCN was already issued by Division VI, covering the period 2014-15 to 2016-17, hence SCN an OIO issued by the Division-VIII is not valid.
- 4. Personal hearing in the case was held on 09.01.2024. Shri Harsh Rashmikant Shah, CA appeared on behalf of the appellant for personal hearing and stated that their client is advocate and not liable to pay service tax. Division VI already dropped the demand. Division VIII again issued the SCN and passed the order which is illegal and without jurisdiction.

- 5. I have carefully gone through the facts of the case, grounds of appeal, submissions made in the Appeal Memorandum and documents available on record. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order passed by the adjudicating authority, confirming the demand of service tax against the Appellant along with interest and penalty, in the facts and circumstance of the case, is legal and proper or otherwise. The demand pertains to the period F.Y. 2015-16.
- 6. Accordingly, I find that the following issues are required to be decided by me (1) whether the activity carried out by the appellant falls under the taxable category or otherwise in terms of the provision of Act, (2) whether the Service Tax has been correctly demanded, (3) whether the appellant the contention of the appellant that the services provided by them are exempted as per Notification No. 25/2012 dated 20.06.2012 is sustainable or not.
- 7. I find that the appellant submitted that Div. VI, CGST & Central Excise, Ahemdabad South has already issued a Show Cause Notice No. V/WS06/O&A/SCN-172/2020-21 dated 24.09.2020 for the period F.Y. 2014-15, 2015-16 and 2016-17. The aforesaid SCN issued from Div. VI, CGST & Central Excise, Ahemdabad South has already been adjudicated wherein the proceedings initiated against the appellant was dropped on the basis of their submission in Division VI that the appellant, a registered advocate with the Bar Council of Gujarat, had submitted defense documents, including an Advocate Certificate, Income Tax Returns, Form 26AS, and financial statements, for the period from FY 2014-15 to 2016-17. The advocate had shown legal fees income in the mentioned years. The analysis of Form 26AS (TDS certificate) in which TDS was found to be deducted under section 194J of the Income Tax Act, 1994 revealed that the appellant had rendered professional service. The appellant's sample invoices also indicated the provision of legal

consultancy services, supporting their claim that they provided legal service during the FY 2014-15 to 2016-17. Now the impugned order passed by the adjudicating authority seems to be just another demand order for the period 2015-16. Due to the above finding, I find that the appellant is not liable to pay service tax as they provided advocate service and hence they are exempted from the liability of service tax under the Notification No. 25/2012-ST dated 20.06.2012. Consequently the question of interest and penalties also does not arise.

- 8. Accordingly, the impugned order is set aside and the appeal is allowed.
- 9. अपील कर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है |
 The appeal filed by the Appellant stands disposed of in above terms.

ज्ञानचंद जैन आयुक्त (अपील्स) Date: ्रे 0.01.2024

STATE COMMANDER OF THE COMMANDER OF THE

िश्मरेंद्र कुमार) अधीक्षक (अपील्स) सी.जी.एस.टी, अहमदाबाद

BY RPAD/ SPEED POST

To M/s. Rajesh Govindbhai Mehta, B-104, Tulip Citadel, Near Shreyas Railways Ambawadi, Ahmedabad – 380 015

Copy to:

- 1. The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone.
- 2. The Principal Commissioner Central GST, Ahmedabad South.
- 3. The Deputy Commissioner, CGST, Division VIII, Ahmedabad South
- 4. The Deputy/Assistant Commissioner (RRA), Ahmedabad South
- 5. The Asstt. Commissioner (HQ System) Central GST, Ahmedabad South (for uploading the OIA).

6. Guard File.

7. P.A. File.

